सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769 www.swarajindianews.com swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्य: ₹ 02

# स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, शनिवार, 30 अगस्त, 2025
वर्ष: 02, अंक: 229, पृष्ठ: 8+4

**कोर्ट ने किया ख़ारिज, अब ट्रंप के टैरिफ का क्या होगा?** » Pg 12

**इनसाइड** जिला सूचना कार्यालय दफ्तर या फिर खंडहर?... » Pg 03

# कानपुर में फिर सक्रिय हुआ डीजल माफिया

खोखली बोलेरो में मौजूद अमन पाल

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

**कानपुर।** कानपुर में सक्रिय डीजल तस्कर कभी बरौनी पाइपलाइन में छेद कर डीजल चोरी करते हैं तो कभी रेल डिब्बे के टैंकरों से डीजल चोरी करते हैं। लगातार ऐसी खबरें और सूचनाओ के बाद भी इन माफिया पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से यह माफिया फिर से कानपुर और आसपास के जिलों में सक्रिय होकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं।

इनपुट के अनुसार कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के पामा चौकी अंतर्गत गोगोमऊ गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो के टैंकरों और तेल वाहक मालगाड़ियों से चोरी करने वाले गैंग के कारण डीजल तस्करी का धंधा बेखौफ जारी है। यह अवैध कारोबार टिकरा पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी महेंद्र पाल और उसका बेटा अमन पाल चला रहे हैं। पहले बोलेरो (UP77-P 5269) पर पुलिस का लाल-नीले रंग का लोगो चिपकाकर डीजल सप्लाई की जाती थी, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। अब लोगो हटा दिया गया है, लेकिन नंबर प्लेट पर कीचड़ लगाकर बोलेरो गाड़ी अभी भी अवैध डीजल के कैनों से लदी सड़कों पर खुलेआम दौड़ रही है।

खचाखच भरे चोरी के डीजल-पेट्रोल के कैन।

पुलिस का लोगो लगाकर हो रही कानपुर में डीजल तस्करी

शहर से देहात तक निडरता से हो रही तस्करी | गोगोमऊ से टिकरा तक फैला सिंडिकेट का जाल

एक्सक्लूसिव

खोखली बोलेरो में लदे अवैध डीजल के कैन

स्वराज इंडिया ने डीजल तस्करी खुलासा पहले भी किया था।

**पुलिस कार्रवाई के बाद भी पिता पुत्र का गैंग सक्रिय :** स्वराज इंडिया ने कुछ महीने पहले खुलासा किया था कि कानपुर के पनकी और सचेंडी थाना क्षेत्र में मालगाड़ी से डीजल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ था। उस समय शिवली और शिवराजपुर पुलिस ने भी कार्रवाई कर कई तस्करों को जेल भेजा था। इसी दौरान टिकरा निवासी महेंद्र पाल और उसका बेटा अमन पाल भी डीजल तस्करी में शामिल पाए गए थे। कुछ समय तक इन लोगों ने धंधा रोक दिया था, लेकिन अब फिर से सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में सामने आए वीडियो और तस्वीरों में साफदिखाई दे रहा है कि बोलेरो गाड़ी पूरी तरह से कैनों से भरी हुई है और उसमें अमन पाल अपने साथी के साथ मौजूद है। गौरतलब है कि यह डीजल चोरी का मालगाड़ी से लाया गया माल होता है, जिसे कानपुर से बिठूर, परियर और सफीपुर तक सप्लाई किया जाता है। गाड़ी कई पुलिस चौकियों से होकर गुजरती है, मगर कार्रवाई न होना विभागीय मिलीभगत पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिसिया चौकियों से अवैध डीजल से भरी गाड़ियां बेरोकटोक निकल रही हों, तो संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है।

## सौ से ज्यादा आतंकियों की करवा चुका है भारत में एंट्री

# मारा गया आतंकी 'समंदर चाचा' उर्फ 'ह्यूमन जीपीएस'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**श्रीनगर।** आतंकियों की दुनिया में बागू खान उर्फ समंदर चाचा को 'ह्यूमन जीपीएस' भी कहा जाता था। क्योंकि, उसे गुरेज सेक्टर के दुर्गम इलाकों और गुप्त रास्तों की अच्छी जानकारी थी। बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में समंदर चाचा के साथ एक और पाकिस्तानी घुसपैठिया भी ढेर हुआ है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है।

सूत्रों के अनुसार बागू खान हिजबुल का कमांडर था और 1995 से पाक अधिकृत कश्मीर में तैनात था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, वह उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर के कई इलाकों में 100 से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में शामिल रह चुका है, जिनमें से ज्यादातर मामलों में उसे कामयाबी मिली है। बागू खान को दुर्गम और गुप्त रास्तों की अच्छी जानकारी थी।

## राहुल द्रविड़ ने कोच पद से दिया इस्तीफा

**नई दिल्ली।** टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ अब राजस्थान रॉयल्स से अलग हो गए हैं। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने ये बड़ा ऐलान किया है। फ्रैंचाइजी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के लिए बतौर खिलाड़ी 46 मैच खेले थे। पिछले साल वे राजस्थान रॉयल्स से जुड़े थे।

**खतरे में जान** | **इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश**

# 'राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने वाले को सुरक्षा दी जाए'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

» एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पूर्ण रूप से उपलब्ध कराए

» राहुल गांधी पर कई मामले दायर कराने के कारण है जान का खतरा

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तुरंत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से उपलब्ध कराए।

शिकायत करने वाले व्यक्ति ने ये भी दावा किया है कि वह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और लोकसभा में विपक्ष के

नेता राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले दायर करने और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने के कारण लगातार खतरे में भी बने हुए है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही दिया गया। शिशिर का ये भी कहना है कि वह भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक स्टेट विंग से जुड़े हुए भी हैं। शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं भी दायर की हैं। शिशिर का ये भी कहना हैं कि उन्होंने जून 2024 में लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में एंटी-करप्शन-II ब्रांच, नई दिल्ली को ट्रांसफर भी कर दिया गया।

# कार में मिला सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का शव

» पत्नी से विवाद के बाद स्टेशन पहुंचे, 12 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही कार

» कानपुर के सेंट्रल स्टेशन परिसर में हड़कंप, जीआरपी ने कराया पोस्टमार्टम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड पार्किंग एरिया में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब 12 घंटे से खड़ी एक कार में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर निर्मल उपाध्याय (38 वर्ष) का शव मिला। पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) निवासी और पुलवामा में तैनात इंस्पेक्टर निर्मल 12 दिन पहले कानपुर के साकेत नगर स्थित ससुराल आए थे। रात पत्नी से विवाद के बाद वे शुक्रवार सुबह किराएदार संजय चौहान के साथ कार से स्टेशन पहुंचे थे।

देर शाम तक जब कार पार्किंग में जस की तस खड़ी रही तो संचालक को शक हुआ। उसने झांककर देखा तो ड्राइविंग सीट के पास इंस्पेक्टर का शव पड़ा था और सीट बेल्ट लगी हुई थी। तुरंत जीआरपी को सूचना दी गई।

**शादी के नौ महीने बाद ही रिश्तों में दरार, घरेलू विवाद बना तनाव की वजह**

इंस्पेक्टर निर्मल की शादी 27 नवंबर 2023 को कानपुर निवासी राशि के साथ हुई थी। पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि पति शराब के लती थे और नशे की हालत में मारपीट करते थे। इसी वजह से वह बीते कई दिनों से मायके में रह रही थीं। करीब 12 दिन पहले मेडिकल लीव पर आए निर्मल ने फिर शराब के नशे में हंगामा किया और पत्नी के साथ मारपीट की थी। परिजनों ने बीच-बचाव किया तो अगले दिन सुबह वह किराएदार के साथ स्टेशन पहुंच गए।

किराएदार संजय ने कार पार्किंग में खड़ी कर दी और घर लौट आया। उसने परिवार को बताया कि निर्मल ड्यूटी पर जाने की बात कहकर स्टेशन आए थे। लेकिन जब शाम तक कार नहीं हिली तो पार्किंग संचालक ने गाड़ी चेक की। खिड़की से झांकने पर उनका शव सीट बेल्ट के सहारे लटका दिखा। मौके पर पहुंची जीआरपी और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

# पत्नी से बात करते हुए युवक ने की आत्महत्या

» सूचना पर भी नहीं आई विवाहिता, बोली तेरहवीं की तारीख बता देना

## शादी के डेढ़ माह बाद ही पत्नी मायके से नहीं लौटी, विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कैंट थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शादी के महज डेढ़ माह बाद ही पति ने पत्नी से फोन पर बातचीत के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान संजय नगर खलवा निवासी 28 वर्षीय विजय के रूप में हुई है, जो मेस्टन रोड स्थित कपड़े की दुकान में काम करता था।

परिजनों ने आरोप लगाया कि पत्नी शालू का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग था, इसी कारण वह चौथी के बाद से मायके में रह रही थी और ससुराल लौटने से लगातार इंकार कर रही थी। परिजनों के मुताबिक, विजय बार-बार उसे फोन कर मनाता रहा, लेकिन शालू ने आने से मना कर दिया। गुरुवार देर रात फोन पर विवाद के दौरान विजय ने धमकी दी कि अगर वह नहीं आई तो वह जिंदा नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद विजय ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।

**कान में इयरबड्स लगे मिले, दरवाजा तोड़कर निकाला शव**

घटना के समय घर पर विजय अकेला था। भाभी कंचन बेटे को डॉक्टर को दिखाने गई थीं। शाम को घर लौटीं तो दरवाजा बंद मिला और विजय की चप्पल बाहर पड़ी थी।

कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो विजय का शव फंदे पर लटका मिला। हैरानी की बात यह रही कि उसके कान में इयरबड्स लगे हुए थे और फोन कॉल चालू था।स्वजन का कहना है कि विवाहिता और उसके परिवार ने जल्दबाजी में रिश्ता किया था क्योंकि युवती का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

मृतक की फाइल फोटो

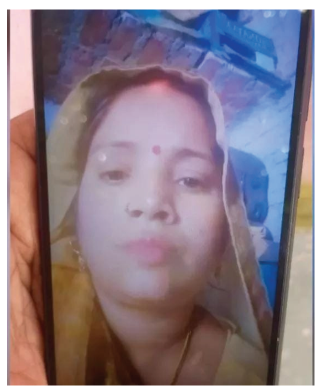

वीडियो कॉलिंग पर मौजूद पत्नी

जब विजय के मौत की सूचना शालू को दी गई तो उसने आने से साफ मना कर दिया और कहा तेरहवीं की तारीख बता देना, तभी आऊँगी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

# जिला सूचना कार्यालय दफ्तर या फिर खंडहर?

**प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया**

**कानपुर।** उत्तर प्रदेश सरकार का अहम विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिस पर सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े संदेश जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है, उसका ही जिला सूचना कार्यालय कानपुर में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।

स्मार्ट सिटी का तमगा पहन चुके कानपुर नगर का यह जिला सूचना कार्यालय, ऐतिहासिक गांधी भवन, फूलबाग में संचालित है लेकिन आलाधिकारियों की घोर उदासीनता और लापरवाही ने इसे जर्जर ढांचे में तब्दील कर दिया है।दीवारों में चौड़ी दरारें, छत से लगातार टपकता पानी, पुराने उपकरण, टूटी कुर्सियाँ और भयावह माहौलज यही है जिला सूचना कार्यालय की असली तस्वीर। यहां तैनात कर्मचारी रोजाना जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर हैं। हालात यह हैं कि फाइलें संभालना तक जोखिम भरा हो गया है।

## अनकहे दर्द से कराहता कानपुर मण्डल का जिला सूचना कार्यालय

## आलाधिकारियों की लापरवाही ने बनाया फूलबाग स्थित दफ़्तर को खंडहर!

### अधिकारी बने मूकदर्शक हादसे का इंतजार

कर्मचारियों और जिम्मेदार नागरिकों द्वारा वर्षों से शासन-प्रशासन को पत्र भेजे गए कि आधुनिक सूचना संकुल का निर्माण किया जाए, जिसमें कार्यालय, मीडिया केंद्र, प्रशिक्षण कक्ष और आवासीय सुविधाएं हों। लेकिन अफसरशाही की फाइलें कागज़ी खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाईं। पत्रों के जवाब तो आए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया के पूर्व सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्याम सिंह पंवार ने कहा कि विभागीय उदासीनता एवं मानवाने राव के चलते जिला सूचना कार्यालय आज बदहाली का शिकार है जबकि इस संबंध में कई बार शासन स्तर से जमीन उपलब्ध कराने के लिए बजट जारी किया गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

### जर्जर इमारत के नीचे बैठे कर्मचारियों में दहशत

कार्यालय की बदहाली केवल भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यकुशलता पर पड़ रहा है। भय के साए में काम करने से उनकी दक्षता घट रही है, और यह पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहा है।

कई विभागीय समीक्षा बैठकें जिलाधिकारी और मंडलायुक्त स्तर पर होती हैं, लेकिन फूलबाग स्थित जिला सूचना कार्यालय की दुर्दशा पर चर्चा तक नहीं होती।

सवाल यह है कि क्या अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं?स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों की मांग है कि तत्काल सूचना संकुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। साथ ही सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं–जैसे सीसीटीवी कैमरे और गार्ड–भी उपलब्ध कराई जाएं।

## बिरहाना लूट की पटकथा फ्लॉप, बोले कोतवाल

# 'पहले दिन से ही कहानी संदिग्ध लग रही थी'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**बिल्हौर (कानपुर)।** कोतवाली क्षेत्र के बिरहाना गांव में जिस फिल्मी अंदाज की दिन दहाड़े हुई लूट ने गुरुवार को पूरे इलाके को दहला दिया था, वह अब फर्जी कहानी साबित होती दिख रही है। कोतवाल अशोक कुमार सरोज ने खुलासा किया है कि बिरहाना गांव की कथित फिल्मी लूट पहले दिन से ही पुलिस की नजर में संदिग्ध थी। उन्होंने कहा, मामला शुरू से ही बनी-बनाई कहानी लग रहा था, अब सच सामने आ रहा है। महिला ने झूठी कहानी क्यों गढ़ी और इसके पीछे कौन लोग थे, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। मालूम हो कि गांव की रहने वाली रोशनी ने दावा किया था कि पारिवारिक सदस्यों की गैरमौजूदगी में दो महिलाएं लाल और नीली साड़ी पहने घर में घुसीं। एक महिला ने चारपाई पर लेटी बिटिया को हथियार दिखाकर धमकाया, दूसरी ने सिर पर डंडे से हमला कर बेहोश किया और फिर अलमारी से सोने की झुमकी, माला, चांदी की पायल, तोड़ियां और करीब तीन हजार रुपये नकद लेकर नौ दो ग्यारह हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया और पूरे इलाके में फैली जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। लेकिन पुलिस की गहन जांच में कहानी के तार बिखरने लगे। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौके की बारीकी से जांच की पर वारदात की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहीं, महिला के मेडिकल में भी सिर्फ सतही चोटें पाई गईं।

सूत्रों का कहना है कि जब पुलिस के सवाल-जवाब में महिला बार-बार उलझी तो उसने खुद ही रिपोर्ट लिखाने से इंकार कर दिया। इसी वजह से पुलिस का शक और गहरा गया और सच में बदल गया।

फिलहाल पुलिस की एक खुफिया टीम यह पता लगाने में जुटी है कि महिला ने इतनी बड़ी कहानी क्यों गढ़ी और क्या इसके पीछे किसी तीसरे व्यक्ति या दबाव की भूमिका रही। कोतवाल का कहना है कि जल्द ही पूरे प्रकरण का सच उजागर किया जाएगा। गांव में अब सिर्फ यही चर्चा है बिरहाना की लूट सचमुच की वारदात थी या महज एक सोचा-समझा ड्रामा।

### कैसे टूटी कहानी की पोल

- **बयान बनाम हकीकत :** पुलिस सूत्रों की मानें तो महिला के बयान घटनास्थल से मेल नहीं खा रहे थे।
- **सतही चोटें :** मेडिकल जांच में गंभीर चोटों का सबूत नहीं मिला।
- **बदलते बयान :** पूछताछ में महिला बार-बार उलझती गई।
- **फोरेंसिक जांच :** घर से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो लूट की पुष्टि करे।

» मेडिकल रिपोर्ट में चोटें मामूली, फोरेंसिक टीम को भी पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, पुलिस कर रही गहराई से जांच

## चोरों की अफवाह में फंसा दोस्त, ग्रामीणों ने खम्भे से बांधा

चोर समझकर ग्रामीणों द्वारा बिजली के खम्भे से बांधा गया युवक।

चौबेपुर। चौबेपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात चोरों की अफवाह ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। जन्मदिन पार्टी से नाराज होकर निकले युवक को ग्रामीणों ने चोर समझ बिजली के खम्भे से बांध दिया। पुलिस पहुंची तो मामला दोस्तों की आपसी कहासुनी और गलतफहमी का निकला। जानकारी के मुताबिक कन्नौज निवासी आलोक दुबे अपने चार दोस्तों संग रमय्या होटल जन्मदिन मनाने आए थे। शराब पीते समय विवाद हो गया और सिद्धांत राय गुस्से में होटल छोड़कर अकेले पैदल हाईवे की ओर निकल गया। रात करीब ढाई बजे ग्राम भवानीपुर में पानी पीते वक्त ग्रामीणों को वह संदिग्ध लगा और चोर समझकर पकड़ लिया। इसके बाद बिजली के खम्भे से बांध दिया। सूचना पर चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुँची और युवक को छुड़ाकर थाने लाई। पूछताछ में साफ हुआ कि यह घटना महज आपसी नाराजगी और अफवाह का नतीजा थी।

## आरपीएस गौरव इंटरनेशनल स्कूल में खेल दिवस पर जोश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करतीं प्रिंसिपल लकी जैन।

**बिल्हौर(कानपुर)** मकनपुर स्थित आरपीएस गौरव इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय खेल दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष असेंबली में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देकर हुई। छात्रों ने भाषण, स्किट और विचार प्रस्तुत कर खेलों का महत्व बताया। प्रिंसिपल लकी जैन ने कहा कि खेल अनुशासन और टीमवर्क सिखाते हैं, जबकि डायरेक्टर आरती कटियार ने खेलों को शिक्षा का अहम

राष्ट्रीय खेल दिवस | प्राथमिक विद्यालय नैला में किया गया कार्यक्रम का आयोजन

# राष्ट्रीय खेल दिवस पर याद किए गए मेजर ध्यानचंद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**बिल्हौर/रसूलाबाद(कानपुर)।** हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले स्वतंत्र भारत के पद्मभूषण मेजर ध्यानचंद के 119वें जन्मदिवस पर शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय नैला में राष्ट्रीय खेल दिवस बड़े उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव द्वारा मेजर ध्यानचंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने से की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद का जीवन अनुशासन, समर्पण और खेल भावना का अद्भुत उदाहरण है, जिसे नई पीढ़ी को प्रेरणा स्वरूप अपनाना चाहिए। इसके बाद विद्यालय प्रांगण में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़, कबड्डी, रस्साकसी समेत कई खेलों में नन्हे-मुन्ने बच्चों की प्रतिभा देखते ही बन रही थी। प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को इंचार्ज प्रधानाध्यापक आलोक कुमार ने पुरस्कार और मिष्ठान वितरित कर सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं, जो न केवल शारीरिक विकास बल्कि टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ बृजमोहन सिंह, संकुल प्रभारी सलिल द्विवेदी, शैलेंद्र सिंह, दिनेश यादव, गगन कुमार, अरुण कुमार समेत समस्त विद्यालय स्टाफ की सक्रिय उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया।

जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव ने बच्चों को किया खेलों के लिए प्रेरित

खेलों में नन्हे-मुन्ने बच्चों की प्रतिभा देखते ही बन रही थी

राष्ट्रीय खेल दिवस पर नैला प्राथमिक विद्यालय में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते अतिथि व विद्यालय परिवार।

## सम्पादकीय

# छात्र जीवन संकट सिस्टम की नाकामी

निस्संदेह, किसी छात्र की आत्महत्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की संस्थागत विफलता ही है। यदि शिक्षा व्यवस्था सतर्क-संवेदनशील रहे तो इन संभावनाओं को असमय काल-कवलित होने से बचा सकते हैं। आंध्रप्रदेश की एक 17 वर्षीय नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर मार्गदर्शक टिप्पणियां की हैं। छात्रों का जीवन बचाने हेतु इस सुप्रीम गाइडलाइंस में पीठ ने देशभर के स्कूल, कालेजों और कोचिंग संस्थानों के लिये गाइडलाइंस जारी की। दरअसल, न्यायाधीश वर्ष 2022 के लिए एनसीआरबी की उस रिपोर्ट से व्यथित थे, जिसमें दर्शाया गया कि इस साल आत्महत्या करने वाले 1,70,924 लोगों में 13,044 छात्र भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का मकसद जानकारी देना ही नहीं है, इसका उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना भी है। निस्संदेह, शिक्षा का मकसद छात्रों का बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि शिक्षण संस्थाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकताएं बनाएं। यह भी कि मानसिक स्वास्थ्य, अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। पीठ ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों के लिये पंद्रह दिशा-निर्देश तय किए हैं, जो इस बाबत कानून बनाने तक ये गाइडलाइंस बाध्यकारी होंगी।

निःसंदेह, सुप्रीमकोर्ट पीठ के ये दिशा-निर्देश उपचारक साबित हो सकते हैं। इसमें प्रत्येक शिक्षण संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाने और विशेषज्ञ नियुक्त करने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति व कार्यक्रमों को इस नीति में शामिल करना होगा। साथ ही जहां सौ से अधिक छात्र हों, वहां मनोवैज्ञानिक व काउंसलर नियुक्त करने होंगे। छात्रों में हीन भावना न आए, इसलिये कोचिंग संस्थान शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर कोई बैच न बनाएं। शिक्षकों व स्टाफ को वर्ष में दो बार छात्रों में आत्महत्या के संकेत पकड़ने व मानसिक स्वास्थ्य के बाबत प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।

सुनिश्चित हो कि समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों व शारीरिक अपूर्णता से जूझ रहे छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव न होने पाए। शिक्षण संस्थान व कोचिंग के परिसर में रैगिंग, यौन उत्पीड़न तथा किसी तरह के भेदभाव से निपटने के लिये समिति बने। साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अभिभावकों को सचेत किया जाए कि वे छात्रों पर अंकों का दबाव न बनाएं और मानसिक तनाव के प्रति संवेदनशील रहें। संस्थान सालाना आधार पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट हर साल यूजीसी को दें। इसके साथ ही खेल, कला व व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। सतर्कता हेतु हॉस्टलों को सुरक्षित बनाने तथा छत, बालकनी, पंखे जैसे स्थानों पर सेफ्टी डिवाइस लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

# नये अवसरों के सृजन को गंभीर पहल जरूरी

**क्षमा शर्मा**

**इस समय देशभर में मिशन मोड में नई सरकारी नियुक्तियां करने और नए रोजगार मौके सृजित किए जाने की अहम जरूरत है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा कौशल विकास में भारी निवेश की ज़रूरत है देश के राज्यों और केंद्र स्तर पर निकलने वाली सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की फेज-13 सेलेक्शन पोस्ट 2025 के अंतर्गत 2423 पदों की भर्ती के लिए पूरे देश से 29 लाख से अधिक आवेदन आए हैं।**

पिछले वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जो भर्तियां की हैं, वे रिक्त पदों की तुलना में बहुत कम हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी नवीन श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के आंकड़ों के मुताबिक 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर जून 2025 में तेजी से बढ़कर 15.3 रही। यह शहरों में बढ़कर 18.8 प्रतिशत रही जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 13.8 प्रतिशत रही है।फ्रांस के कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्सि एसए के द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिस तेजी से युवा रोजगार के लिए तैयार होकर श्रम शक्ति (वर्क फोर्स) में शामिल हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को 2030 तक प्रति वर्ष 1.65 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसमें से करीब 1.04 करोड़ नौकरियां संगठित सेक्टर में पैदा करनी होंगी। जबकि पिछले दशक में सालाना कुल 1.24 करोड़ नौकरियां ही पैदा हो सकी थीं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी को बरकरार रखने के लिए सर्विसेज से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी सेक्टर्स को नई रफ्तार से बढ़ावा देना होगा ऐसे में इस समय देशभर में मिशन मोड में नई सरकारी नियुक्तियां करने और नए रोजगार मौके सृजित किए जाने की अहम जरूरत है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा कौशल विकास में भारी निवेश की ज़रूरत है, जिससे देश के जनसांख्यिकीय लाभ को हासिल करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कौशल विकास के लिए निवेश का बोझ सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों को मिलकर उठाना होगा। भारत के पास अभूतपूर्व अवसर हैं, क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल की भारी कमी का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंच पर भारत की कार्यबल क्षमता को उजागर करने के लिए कौशल विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। वित्त वर्ष 2015 से अब तक कॉर्पोरेट्स द्वारा सीएसआर पर खर्च किए गए 2.22 लाख करोड़ रुपये में से केवल 3.5 प्रतिशत ही कौशल विकास के लिए खर्च किया गया है। ऐसे में सीएसआर निवेश को अलग-थलग कौशल गतिविधियों से आगे बढ़ना होगा। जब सरकारी पहलों के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत किया जाता है, तो सीएसआर में एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करने की अपार क्षमता होती है।

सरकार को देश की नई पीढ़ी को जॉब सीकर यानी नौकरी की चाह रखने वाले से ज्यादा नए दौर के जॉब गिवर यानी नौकरी देने वाले बनाने की तेज रणनीति के साथ भी आगे बढ़ना होगा। देश में स्वरोजगार की रफ्तार बढ़ाई जानी होगी।

# एक्सपायरी दवाओं से बढ़ता पर्यावरणीय संकट

## निस्तारण की समस्या

**डा0 जगदीप सिंह**

**एक्सपायरी दवाओं का गलत निपटान पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इनके सुरक्षित निस्तारण और इस दिशा में जागरूकता बढ़ाना समाज की जिम्मेदारी है, ताकि दवा अपशिष्ट से होने वाले दुष्प्रभाव रोके जा सकें।खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, सभी दवाओं पर समापन तिथि अंकित होना अनिवार्य है। निर्माता आमतौर पर दवा की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समापन तिथियों का रूढ़िवादी अनुमान प्रदान करते हैं। एक्सपायर दवाइयां रखना अथवा इनका सेवन करना जितना ज़ोखिमपूर्ण हो सकता है, उससे कहीं अधिक घातक सिद्ध होता है इनका असुरक्षित निपटान। एक अध्ययन के मुताबिक़ 60 प्रतिशत से अधिक लोग निस्तारण निर्देशों से सर्वथा अपरिचित हैं।**

भारतवर्ष में 'बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016' के आधार पर अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लैब और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों को अपने यहां उत्पन्न होने वाला मेडिकल वेस्ट सुरक्षित तरीके से एकत्रित करके अधिकृत ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचाना होता है। नियमों के तहत, फार्मेसियों तथा अस्पतालों में भी दवाओं के लिए अलग से मेडिसिन ड्रॉप बॉक्स-कंटेनर आदि रखे जा सकते हैं, जिससे रोगी पुरानी या एक्सपायरी दवाइयां लौटा सकें।घरेलू स्तर पर अनुपयोगी दवा निस्तारण संबद्ध व्यवस्था खंगालें तो इस संदर्भ में कोई स्पष्ट नीति नहीं। वास्तव में, देश के अनेक शहरों में अभी तक कोई आधिकारिक या व्यवस्थित सिस्टम नहीं बन पाया। न तो एक्सपायर दवाइयों को निपटाने हेतु कोई ठोस संग्रहण नीति बनी है, न ही अपेक्षित सतर्कता को लेकर पर्याप्त जन-जागरूकता अभियान ही चलाए जाते हैं। कतिपय प्रयत्न यदि होते हैं तो अधिकतर निजी संस्थानों या समाजसेवकों के हवाले से ही।एक्सपायरी दवाइयां समय के साथ विषाक्त रसायनों में परिवर्तित होने लगती हैं। समुचित निस्तारण न हो तो इनका दुष्प्रभाव समूचे पर्यावरण को विषैला बना सकता है। ज्यादातर मामलों में दवाएं शौचालय में बहाना जीवों, पर्यावरण और जलापूर्ति के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। बावजूद इसके, 2020 की एक शोध-समीक्षा के मुताबिक़, अनुपयोगी दवा निपटान प्रबन्धन के अभाव के चलते, कई देशों में रोगियों द्वारा पुरानी-एक्सपायरी दवाएं कचरे में फेंकना अथवा सीवर में बहाना निस्तारण का सबसे आम तरीका पाया गया।भारत के बड़े शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है। कूड़े के ढेर में मुंह मारते आवारा पशु अथवा कुत्तों-कौओं के झुंड भक्ष्य पदार्थों की खोज में अक्सर असावधानीपूर्वक फेंकी गई दवाएं भी निगल जाते हैं। शरीर के लिए अहितकारी रसायनों से उनकी मौत तक हो सकती है। सिंक या शौचालय में बहाई दवाइयां शहर के सीवरेज़ सिस्टम से होती हुई नदियों और भूमिगत जल में जा मिलती हैं। दवा में मौजूद विषाक्त रसायन जहां मिट्टी की उर्वरकता प्रभावित करते हैं, वहीं इससे पेयजल दूषित होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।सीवेज सिस्टम में मौजूद दवाओं के तत्व जलीय जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। जलापूर्ति में दवाओं की न्यूनतम मात्रा भी मानव स्वास्थ्य के लिए ख़तरा उत्पन्न करती है। कुछ दवाएं एंडोक्राइन डिसरप्शन का कारण बन सकती हैं, इससे मछलियों और मनुष्यों में हार्मोनल असंतुलन देखा गया। पानी में दवाओं की सूक्ष्म मात्रा एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध बढ़ा देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट मानता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है।अप्रयुक्त दवाइयों के निपटान का सर्वोत्तम तरीका है, अपने आस-पास स्थित किसी दवा वापसी केंद्र का इस्तेमाल करना। भारत में कुछ प्राइवेट फार्मेसियां यह सुविधा देती हैं।

# कानपुर: राजमार्ग पर खराब पड़ी एलईडी लाइटों से राहगीर परेशान

## अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ा खतरा

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर। शहर के जरौली फेज-2 वार्ड 82, जोन-3 क्षेत्र के निवासी राजेश बाबू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र भेजकर राजमार्ग पर खराब पड़ी एलईडी लाइटों की समस्या को उठाया है।**

शिकायत के अनुसार, राम गोपाल चौराहा बर्रा–8 से आनंद साउथ सिटी कटियार मेडिकल स्टोर तक लगी अधिकांश एलईडी लाइटें पिछले एक महीने से खराब पड़ी हैं।

केवल दो–तीन लाइटें ही जल रही हैं, जबकि 33 एमआईजी लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से लेकर 37 एमआईजी सोम टाइल्स तक लगातार अंधेरा छाया रहता है।

राहगीरों का कहना है कि अंधेरे के कारण रात में आवागमन बेहद कठिन हो गया है, चोरी–छिनैती की घटनाएं बढ़ रही हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

Track Grievance

Applicant name - Rajesh Babu
Father / Husband name - Ram Awtar
Mobile number 1 - 7268868788
Address - Ward - JARAULI,Tehsil - कानपुर सदर,District - कानपुर शहर

Application details

Complaint No - 40016425064130
Complaint Type - शिकायत
Complaint Date - 30-08-2025
Complaint Status - लंबित
Application details
सेवामें, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार विषयः राजमार्ग पर लगी खराब एलईडी लाइटों की मरम्मत के संबंध में अधिकारियों द्वारा सुनवाई न करने के बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं राजेश बाबू जरौली फेज 2, वार्ड 82, जोन 3, कानपुर का निवासी हूँ। राम गोपाल चौराहा बर्रा 8 से कटियार मेडिकल स्टोर नियर ...

View More

SEND REMINDER

राजेश बाबू ने बताया कि उन्होंने पहले पार्षद से लाइटें सही करवाने का अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके बाद नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, जहाँ एक सप्ताह में लाइटें ठीक करने का आश्वासन दिया गया। किंतु महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इतना ही नहीं, 13 अगस्त को जोन–3 किदवई नगर के राजमार्ग अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन वादा करने के बावजूद अब तक लाइटें दुरुस्त नहीं की गईं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और अधिकारियों के ढुलमुल रवैए के चलते समस्या जस की तस बनी हुई है।

प्रार्थना पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए

तथा खराब एलईडी लाइटों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।

# रिंग रोड निर्माण की लापरवाही से रास्ता बना तालाब

» **स्कूली बच्चों की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ड्राइवर ने धक्का लगाकर निकाला**

» **रिंग रोड अधिकारी लापरवाह, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा**

**प्रमुख संवाददात/स्वराज इंडिया**

**कानपुर। आउटर रिंग रोड निर्माण के दौरान ठेकेदार कंपनी की लापरवाही अब ग्रामीणों और राहगीरों पर भारी पड़ रही है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव भऊवापुर के नहर पुल के पास बने रास्ते में बारिश का पानी और मिट्टी मिलकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। हालत यह है कि यह रास्ता अब तालाब जैसा नजर आ रहा है।गांव वालों का कहना है कि कंपनी की मनमानी और अफसरों की चुप्पी ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। आए दिन वाहन चालक परेशान होते हैं और कई बार बाइक सवार गड्ढों में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। लेकिन अब तक सुधार के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।**

**स्कूली बच्चों की गाड़ी कीचड़ में फंसी**

गुरुवार को स्थिति और खतरनाक हो गई। स्कूली बच्चों से भरी एक वैन नहर पुल के पास कीचड़ में बुरी तरह धंस गई। गाड़ी चालक ने किसी तरह बच्चों को सुरक्षित रखा और खुद कीचड़ में उतरकर धक्का देकर गाड़ी को बाहर निकाला। आसपास मौजूद लोगों ने इस दृश्य का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

**ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन पर सवाल**

भऊवापुर और आसपास के गांवों के लोग बार–बार शिकायत करने के बावजूद

अधिकारियों की चुप्पी से नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रिंग रोड का काम करने वाली कंपनी मनमानी कर रही है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है।लोगों का कहना है कि बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा खतरे में डालने वाले इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे।अब देखना यह है कि रिंग रोड अधिकारी और जिला प्रशासन इस मामले को कब तक नजरअंदाज करते हैं कहीं ऐसा न हो कि उनकी लापरवाही से कोई बड़ा हादसा घट जाए।

# विवेचक के खेल की कोर्ट में खुल रही पोल

निर्मल तिवारी स्वराज इंडिया

» विवेचक 2 साल जांच के बाद भी नई तलाश पाए फर्जी गवाह

» कोर्ट ने माना न्याय के सिद्धांतों का नहीं हुआ पालन

» विवेचक फर्जी इकरारनामें की वादी से ही मांगते रहे मूल प्रति

» कोर्ट ने माना दौरान विवेचना आरोपी से नहीं की गई गंभीरता से पूछताछ

» कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर अभियुक्तों को तलब किया और दिया स्टेट केस का दर्जा

**कानपुर ।** पिछले 13 महीनों में कानपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर विभिन्न स्तरों पर नामचीन लोगों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई और जांच में एक बात प्रमुखता से उभर रही है कि पूर्व में कुछ विवेचक पुलिस विवेचना में कभी स्वार्थवश तो कभी दबाव वश विवेचना में त्रुटियां कर कुछ लोगों की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करने में संलग्न रहे हैं। वर्तमान समय में ऑपरेशन महाकाल के दौरान भी इस तरह की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है।

विवेचक की दोषपूर्ण जांच का एक ऐसा ही मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में भी चल रहा था इसमें भी न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में विवेचक की विवेचना को त्रुटि पूर्ण मानते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम आख्या को रद्द कर अभियुक्तों को तलब कर लिया है साथ ही मामले को स्टेट केस का दर्जा दिया है।

## पुलिस ने पहले नहीं लिखी एफआईआर फिर लगा दी एफआर

वादी मनोज कुमार वर्मा ने देवेंद्र सिंह तन्ना से 12 लाख 80 हजार का कर्ज लिया, जिसे 6 माह में वापस करना था। जब मनोज कुमार कर्ज अदायगी समय से नहीं कर पाए तो देवेंद्र सिंह ने दबाव बनाकर कर्ज अदा होने तक मनोज कुमार की चौक सर्राफा स्थित खाली दुकान पर बिना लिखा पढ़ी बैठने देने को कहा और आश्वासन दिया पैसा वापस मिलते ही दुकान छोड़ देगा। दबाव में वादी को आरोपी की बात माननी पड़ी। वादी का कहना है कि 14 जून 2018 से 4 जुलाई 2019 तक कई किस्तों में उसने कर्ज अदा कर दिया लेकिन देवेंद्र सिंह तन्ना ने दुकान खाली नहीं की। जब वादी द्वारा दुकान खाली करने को कहा गया तो न केवल आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की बल्कि अपनी महिला मित्र के साथ रात के समय वादी मुकदमा के घर जाकर उठा ले जाने, जान से मार देने, व फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इधर प्रार्थी को आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि देवेंद्र सिंह तन्ना ने कूट रचित दस्तावेज व वादी मनोज के फर्जी हस्ताक्षर कर अनुबंध पत्र बनवा कर टिन नंबर व जीएसटी नंबर प्राप्त कर लिया है। मनोज कुमार ने कोतवाली थाने व पुलिस

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभा शंकर वर्मा

अधिकारियों को प्रार्थना देकर गुहार लगाई, सुनवाई ना होने पर न्यायालय में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर दिनांक 8 अगस्त 2022 को पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज की।

## विवेचक ने लगा दी एफआर

शुरुआत में जहां पुलिस ने मनोज की गुहार को अनसुना कर दिया था, रिपोर्ट नहीं लिखी थी, वहीं यह सिलसिला न्यायालय के आदेश से दर्ज हुई एफआईआर की जांच में भी चलता रहा। दर्ज एफआईआर की विवेचना कोतवाली थाने में उस समय तैनात रहे उप निरीक्षक अविसार सिंह ने की। वादी की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाशंकर वर्मा ने प्रोटेस्ट पिटीशन में दलील दी कि दौरान विवेचना विवेचक वादी मुकदमा से ही इकरारनामे की मूल प्रति मांगता रहा जबकि वादी ने तहरीर में ही इकरारनामा के कूट रचित होने की बात कही थी। इतना ही नहीं विवेचन अविसार सिंह वादी मुकदमा से ही उन दो गवाहों की भी जानकारी मांगते रहे जिनके हस्ताक्षर उस कथित कोर्ट रचित इकरारनामें में थे। विवेचक ने तमाम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को दरकिनार कर आरोपी को लाभ पहुंचाते हुए अंतिम आख्या लगाकर जांच समाप्त कर दी।

## विवेचक द्वारा नजरअंदाज किए गए मुख्य बिंदु

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिनव तिवारी ने अपने आदेश में लिखा कि विवेचक द्वारा बार-बार वादी मुकदमा से किराया अनुबंध पत्र की प्रति मांगी जाती रही जबकि वादी द्वारा बार-बार कहा गया कि अनुबंध पत्र उसके द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। अतः अनुबंध पत्र की मूल प्रति विपक्षी के पास ही है। विवेचक द्वारा अनुबंध पत्र पर दस्तखत करने वाले दो गवाहों को भी दरियाफ्त नहीं किया गया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कहा था कि वह हिंदी में ही हस्ताक्षर करता है समर्थन में पैन कार्ड और पासपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराई, जबकि कूटरचित अनुबंध पत्र में वादी के अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे। इसके साथ ही अनुबंध पत्र में वादी के पिता का नाम भी गलत लिखा गया था। जांच का सबसे विरोधाभासी तथ्य यह रहा कि जांच के दौरान पर्चा नंबर 9 में विवेचक ने स्वयं अभियुक्त का कथन दर्ज किया की मूल किराया अनुबंध उसके अधिवक्ता के पास है फिर भी विवेचक वादी मुकदमा से ही मूल प्रति की मांग करता रहा। जबकि उसे आरोपी से मूल अनुबंध पत्र दाखिल करने का दबाव बनाना चाहिए था।

## न्यायालय एफआर निरस्त कर स्टेट केस का दर्जा दिया

सामान्यतः इस तरह के मामलों में न्यायालय प्रोटेस्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर परिवाद के रूप में दर्ज करता है। लेकिन पुख्ता सबूत की मौजूदगी में मामले को सीधे स्टेट केस के रूप में अंगीकार करता है। इस केस में न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र सिंह उर्फ तन्ना व इकरारनामें में हस्ताक्षर करने वाले गवाहों राकेश सिंह व अमरीश गौर द्वारा धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी आईपीसी के तहत कारित अपराध का संज्ञान लेते हुए, उपरोक्त तीनों को विचरण हेतु तलब किया।

# निराधार साबित हो रहे ग्राम पंचायत में बनाए गए आरआरसी सेंटर

» अफसरों की उदासीनता और प्रधान-सचिव की लापरवाही से ठप योजनाएं

» करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं मिल रहा गांवों को गंदगी से निजात

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर देहात।** ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए रिसोर्स रिकवरी सेंटर अब बेकार साबित हो रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में सेंटर तो बनकर तैयार हैं, लेकिन प्रधान और सचिव संचालन में रुचि नहीं ले रहे। वहीं अफसर भी सुध लेने को तैयार नहीं हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस में रखने और कूड़े के निस्तारण के उद्देश्य से आरआरसी सेंटर बनाए गए थे। इनमें सोकपिट, खाद के गड्ढे और वर्मी कंपोस्ट प्लांट तक तैयार हो चुके हैं। लेकिन कूड़ा गाड़ियां खरीदी नहीं जा रहीं और न ही सेंटरों का संचालन हो रहा है।

डीपीआरओ प्रकाश पटेल

ब्लॉक मलासा की अधिकांश ग्राम पंचायतों में RRC सेंटर अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों खर्च के बाद भी गंदगी जस की तस है। पंचायती राज अधिकारी ग्राम प्रधानों और सचिवों को बार-बार आदेश दे रहे हैं, लेकिन वे संचालन से हाथ खड़े कर रहे हैं।

जिला प्रशासन भी इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा।

सरकार का मानना था कि इन सेंटरों से वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद बनाकर गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खाद की बिक्री से पंचायतों की आमदनी बढ़ती और कर्मचारियों का मानदेय भी निकल आता। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता और अतिरिक्त मेहनत से बचने की प्रवृत्ति ने योजनाओं को ठप कर दिया है।डीपीआरओ विकास पटेल का कहना है कि दिसंबर से बजट का अभाव है, इस कारण कूड़ा गाड़ी खरीद और संचालन रुका हुआ है। उनका दावा है कि बजट मिलते ही सेंटरों का संचालन शुरू कराया जाएगा।स्थानीय लोगों का आरोप है कि अफसर सिर्फ कागजों में योजनाएं पूरी कर दिखा रहे हैं। RRC सेंटर तभी चलते हैं जब कोई निरीक्षण होता है, उसके बाद सब बंद हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अब अफसर भी मीडिया की खबरों पर ही निर्भर हैं और बिना दबाव के गांवों की योजनाओं पर ध्यान नहीं देते।

# कानपुर देहात में व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त

» जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

सीसीटीवी दुरुस्त रखने और गश्त बढ़ाने के दिए गए सख्त निर्देश

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

**कानपुर देहात।** जिले में व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। मां मुक्तेश्वरी सभागार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित अहम बैठक में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंपनियों के संचालक और स्थानीय व्यापारी शामिल हुए।बैठक में व्यापारिक सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपराधिक तत्वों की निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का आदेश दिया।

सीसीटीवी दुरुस्त रखना अनिवार्य पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों से

अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को हर हाल में चालू और दुरुस्त रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान का कैमरा बंद पाया गया तो संबंधित व्यापारी को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी अपराध निवारण और अपराधियों की पहचान का सबसे बड़ा साधन है।

जिलाधिकारी ने जोर दिया कि सुरक्षित और अनुकूल व्यापारिक वातावरण बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को ठोस और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

# कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या

» बेटियों की शादी की चिंता बनी मौत का कारण

» आर्थिक तंगी और कर्ज ने ली विजय नारायण की जान

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में कर्ज से परेशान 46 वर्षीय किसान विजय नारायण ने बीती रात जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान की चार बेटियां और दो बेटे थे। वह अब तक केवल एक बेटी की शादी कर पाया था, बाकी तीन बेटियों की शादी और कर्ज का बोझ उसके लिए असहनीय साबित हुआ।परिजनों के अनुसार विजय नारायण लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। शादी की जिम्मेदारी और कर्ज चुकाने की चिंता से व्यथित होकर उसने यह कदम उठाया। सूचना मिलने पर गजनेर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पिता की मौत से आहत बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा हमारा सहारा कौन बनेगा, पापा हमें क्यों छोड़ गए?ग्रामीणों ने भी बताया कि किसान लंबे समय से परेशान था और आए दिन कर्ज व शादी की चिंता में डूबा रहता था।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

# आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट

» पत्नी ने भाई संग मिलकर पति को पीटा, थाने में दी तहरीर

हलदरपुर और प्रहलादपुर गांव में दो अलग-अलग विवाद, कई लोग घायल

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हलदरपुर और प्रहलादपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते दो अलग-अलग स्थानों पर मारपीट की घटनाएं हुईं। दोनों मामलों में घायलों ने थाने में तहरीर दी है।हलदरपुर गांव निवासी सोनू पुत्र इंद्रपाल ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अजमेरी और कशमीरी गाली-गलौज कर रहे थे। जब उसने रोकने की कोशिश की तो दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी राखी और मां सरला को भी मारपीट कर घायल कर दिया।

इसी तरह, प्रहलादपुर गांव निवासी अरविंद पुत्र कल्याण सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात वह घर पर लेटा था। तभी उसकी पत्नी ममता, साले पिंटू और

उसकी पत्नी पिंकी निवासी सिथरा बुजुर्ग घर पहुंच गए

और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर अरविंद को पीटकर घायल कर दिया।पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

# जीरो डोज इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर कार्यशाला आयोजित

» शून्य से एक वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण पर जोर

» पेंटा-1 डोज के ड्रॉपआउट को कम करने की बनाई गई रणनीति

कानपुर देहात। जिले में बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने और टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पीसीआई इंडिया संस्था द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय जीरो डोज इम्प्लीमेंटेशन प्लान कार्यशाला आयोजित की गई।विशेषज्ञों ने बताया कि 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे उन्हें कई गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। नियमित टीकाकरण से बच्चों को 12 जानलेवा

बीमारियों (जैसे लकवा, खसरा-रुबैला, गलाघोंटू, काली खांसी, नवजात टिटनेस) से बचाव संभव है।कार्यशाला में डॉ. एस.एल. वर्मा (अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी), डॉ. आशीष बाजपेयी (जिला प्रतिरक्षण अधिकारी), डॉ. डी.के. सिंह (उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी), डॉ. हेमंत अधिकारी (एसएमओ डब्ल्यूएचओ) सहित स्वास्थ्य विभाग, पीसीआई इंडिया, यूनिसेफ और यूएनडीपी के अधिकारी व ब्लॉक स्तर के प्रभारी चिकित्साधिकारी मौजूद रहे।कार्यशाला में अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि टीकाकरण बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय है। आम जनता से अपील की गई कि वे अपने बच्चों को टीकाकरण सत्र स्थलों पर अवश्य लेकर जाएं और उन्हें प्रतिरक्षित कर स्वस्थ भविष्य दें।

## चार दिन से अंधेरे में गजनेर: ट्रांसफार्मर जला, ग्रामीणों ने किया पुतला दहन

» बिजली न मिलने से उमस भरी गर्मी में बेहाल ग्रामीण, फूटा गुस्सा

कानपुर देहात,माती। गजनेर कस्बे में चार दिन से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, जिससे करीब दो सौ घरों के एक हजार लोग अंधेरे और भीषण गर्मी में बेहाल हैं। शुक्रवार को नाराज़ ग्रामीणों ने गजनेर बिजली घर के बाहर एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान गुस्साए युवकों ने पुतला दहन कर विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया।

26 अगस्त की रात 10 बजे ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल गया था। 27 अगस्त को शिकायत दर्ज कराने के बाद भी तीन दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। इससे तंग आकर ग्रामीण महिलाओं संग बिजली घर पहुंचे और विरोध किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया।

अवर अभियंता मयंक सिंह राठौर ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर आ गया है और शाम तक लगा दिया जाएगा। पुतला दहन की जानकारी उन्हें नहीं है।

# समाज में अच्छा व्यक्ति खड़ा करना ही संघ का मूल उद्देश्य: क्षेत्र प्रचार प्रमुख

## शताब्दी वर्ष पर आरएसएस के 7 बड़े कार्यक्रम, घर-घर पहुंचेगा जनजागरण, हिंदू सम्मेलन भी होंगे

**प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया**

**कानपुर।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष (100 वर्ष) के उपलक्ष्य में पूरे वर्षभर 7 बड़े कार्यक्रम करने जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में राष्ट्र प्रेम, मानवता, हिंदुत्व, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को मजबूत करना है। यह जानकारी संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख (पूर्वी उत्तर प्रदेश) सुभाष जी ने शुक्रवार को प्रांत कार्यालय केशव भवन में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में दी।**

कानपुर पहुंचे अवध प्रांत के क्षेत्र प्रचार प्रमुख आशीष जी ने मीडिया से साझा किए विचार

उन्होंने कहा कि संघ का मूल कार्य है समाज में अच्छे और आदर्श व्यक्तियों का निर्माण करना। यही लक्ष्य शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में झलकेगा।

सुभाष जी ने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत विजयादशमी उत्सव से होगी, जो 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसमें तरुण स्वयंसेवकों का संचलन, नई भर्ती, पूर्ण गणवेश में उपस्थिति और ग्रामीण व पंचायत क्षेत्रों में जाकर लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा।

**हर गांव मोहल्ले में होंगे जनजागरण और हिंदू सम्मेलन**

1 से 31 दिसंबर तक व्यापक गृह सम्पर्क अभियान चलेगा। इसके बाद 12 जनवरी से 12 फरवरी 2026 तक प्रांत के मंडल और बस्तियों में बड़े हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

अप्रैल में प्रमुख जन गोष्ठी, मई में सामाजिक सद्भाव बैठकें और प्रतिभावान छात्रों के सम्मेलन होंगे। इसी तरह अगस्त-सितंबर में युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और शाखा हमारी शक्ति अभियान चलाया जाएगा।

**राष्ट्रहित और पर्यावरण की सोच**

संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में पर्यावरण संरक्षण को भी प्रमुख लक्ष्य बनाया है। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, पौधरोपण और जल संरक्षण पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

सुभाष जी ने कहा-संघ का सबसे बड़ा स्थान भगवा ध्वज है। शाखाओं को बढ़ाना, समाज को जोड़ना और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना हमारा संकल्प है। चर्चा के दौरान कानपुर प्रांत के अनुपम जी और विभाग प्रचार प्रमुख आशीष प्रताप भी मौजूद रहे।

# पीएम के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में....

- » कानपुर-बुंदेलखंड में बीजेपी महिला मोर्चा करेंगी आंदोलन
- » बिहार में राहुल गांधी की जनसभा में पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी से आहत हैं भाजपाई: प्रकाश पाल
- » क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि महिला मोर्चा कांग्रेस कार्यालयों में करेंगी

**प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया**

**कानपुर।बिहार राज्य में एनडीए की सरकार है। वहां पर नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा डेरा जमाकर हर दिन नए नए मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है।**

प्रकाश पाल भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड

बीते दिन कांग्रेस प्रमुख नेता राहुल गांधी की एक जनसभा में एक मुस्लिम युवक के द्वारा पीएम मोदी की मां के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है।

कानपुर-बुंदेलखंड बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि पीएम मोदी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर 31 से 1 तारीख के बीच हर जिले में महिला मोर्चा की पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेंगी।

श्री पाल ने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल हताशा में है। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए इधर उधर की बातें करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी की कडी निंदा करते हैं और राहुल गांधी उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

# अयोध्या का प्रदूषण विभाग बन बैठा खरदूषण

» जब हवा भी बिकने लगी कीमत पर!

» एनओसी की फाइलों पर ताला, रिश्वत की चाबी से खुलता रास्ता

» 10 से 20 हज़ार रुपये तक की अवैध वसूली – कौन है असली सरगना?

» जिम्मेदार अधिकारी मौन, प्रदूषण बढ़ा, सांसें महंगी हुई

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

अयोध्या। धर्म और आस्था की नगरी अब भ्रष्टाचार के धुएं में घुट रही है। प्रदूषण विभाग, जो हवा और पानी को शुद्ध रखने का जिम्मा उठाता है, वही अब खर-दूषण बन बैठा है। सूत्रों की मानें तो होटल गेस्ट हाउस के एनओसी के नाम पर यहां आने वाले आवेदकों से 10 से 20 हजार रुपये तक की अघोषित वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है। रामनगरी की हवा को शुद्ध रखना जिम्मेदारी है, पर यहां तो हर सांस की कीमत तय कर दी गई है। सूत्र बताते हैं की विभागीय कर्मचारी और कुछ अधिकारी बिना मोटी रकम चढ़ाए किसी को भी एनओसी जारी नहीं करते। नियमों की आड़ में फाइलों को रोका जाता है और आवेदक को मजबूर कर दिया जाता है किचाय-पानी का इंतजाम करे। वसूली की रकम 10,000 रुपये से शुरू होकर 20,000 रुपये तक पहुंच जाती है।

**हवा में घोटाला**-रामनगरी की पवित्र हवा को भी रिश्वत की गंध ने दूषित कर दिया। यहां एनओसी सिर्फ फाइलों से नहीं, जेबों से निकलती है।

**धुआं-धुआं ईमानदारी**-प्रदूषण रोकने वाले अफसरों की ईमानदारी भी अब धुएं में उड़ गई। सवाल यह क्या अगली बार सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा?

**तिजोरी की चाबी पर सांसें**-जहां नियम-कानून दम तोड़ दें और भ्रष्टाचार तिजोरी में सांसें बंद कर दे, वहां कौन बचाएगा रामनगरी की हवा को।

अयोध्या में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और नगर निगम मिलकर काम करेंगे। विश्वविद्यालय अपने वायु गुणवत्ता शोध के नतीजे नगर निगम को देगा जिसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहल से यह संभव हो रहा है। शोध में रामनगरी में नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूल कणों की मात्रा बढ़ने की बात सामने आई है।

**स्वराज इण्डिया के सवाल**

क्या प्रदूषण विभाग में रिश्वतखोरी की जड़ें ऊपर तक फैली हैं?

मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के दावे कागज पर ही क्यों?

कब तक रामनगरी की हवा को इस भ्रष्टाचार की बदबू झेलनी पड़ेगी?अयोध्या में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है भ्रष्टाचार का प्रदूषण। सवाल ये है कि क्या विभाग पर जल्द कार्रवाई होगी या फिर हवा बेचने का यह खेल यूं ही चलता रहेगा?

जब स्वराज इंडिया टीम ने प्रदूषण कार्यालय में जाकर उपरोक्त आरोपो के बारे में जानकारी चाही तो वहां मौजूद एई ओम प्रकाश ने बताया कि हम कोई जानकारी नही दे सकते क्योंकि क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी आर बी सिंह नही है उनके पास दो मंडलो का चार्ज है तो वह आज बस्ती गए है। उनके आने पर ही जानकारी मिल पाएगी।

# रामनगरी में पुश्तैनी मंदिरों पर माफियाओं की नजर

» विद्युत विभाग के अफसरों पर केस दर्ज

» एसडीओ, जेई, लाइनमैन और दलाल पर कोर्ट के आदेश से केस

» अधिवक्ता की लंबी लड़ाई लाई रंग

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

अयोध्या। राम जन्मभूमि के कोटिया मंदिर (रामजानकी गेट नंबर 11) से जुड़े विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर विद्युत विभाग के एसडीओ नवनीत सिंह, अवर अभियंता

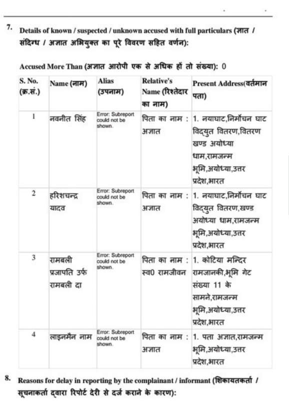

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नवनीत सिंह | Error: Subreport could not be shown. | पिता का नाम : अज्ञात | 1. नयाघाट,निर्मोचन घाट विद्युत वितरण,वितरण खण्ड अयोध्या धाम,रामजन्म भूमि,अयोध्या,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 2 | हरिशचन्द्र यादव | Error: Subreport could not be shown. | पिता का नाम : अज्ञात | 1. नयाघाट,निर्मोचन घाट विद्युत वितरण,खण्ड अयोध्या धाम,रामजन्म भूमि,अयोध्या,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 3 | रामबली प्रजापति उर्फ रामबली दा | Error: Subreport could not be shown. | पिता का नाम : स्व0 रामजीवन | 1. कोटिया मन्दिर रामजानकी,भूमि गेट संख्या 11 के सामने,रामजन्म भूमि,अयोध्या,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 4 | लाइनमैन नाम | Error: Subreport could not be shown. | पिता का नाम : अज्ञात | 1. पता अज्ञात,रामजन्म भूमि,अयोध्या,उत्तर प्रदेश,भारत |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

4

हरिश्चंद्र यादव, लाइनमैन और दलाल रामबली प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।पीड़ित अधिवक्ता अश्वनी कुमार ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को रामबली प्रजापति के कहने पर एसडीओ और जेई ने बिना किसी सूचना के लाइनमैन से मकान का मीटर उखड़वा दिया। मकान वही है जहां उनके पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिर स्थित है।

**केस दर्ज - धाराएं भी गंभीर**

पुलिस ने धारा 319(2), 318(4), 338, 336, 352 और 35 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।अधिवक्ता का आरोप है कि यह पूरा खेल पुश्तैनी मकान को कब्जाने के लिए रचा गया था।पीड़ित ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। रामनगरी में ऐसे तमाम पुश्तैनी मकान और मंदिर भूमाफियाओं के निशाने पर हैं,जिससे सवाल उठ रहा है क्या हर पीड़ित को न्याय पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा?

# मवई सीएचसी:नर्स ने लगाया यौन शोषण और वसूली का आरोप

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

अयोध्या।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग की छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक स्टाफ नर्स ने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर आशुतोष सिंह पर न केवल 10 हजार रुपये की अवैध वसूली बल्कि यौन शोषण के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता नर्स ने जनसुनवाई ऐप पर दर्ज शिकायत में कहा रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बावजूद महीनों तक वेतन रोक दिया गया।

जब विरोध किया तो बीपीएम ने 10 हजार रुपये की मांग की। आरोप है कि इसके बाद वह शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा।लगातार अभद्र हरकतों से नर्स की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा।

**सीएमओ का हस्तक्षेप**

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुशील कुमार बानियान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 28 जून को जांच आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला मलेरिया अधिकारी को प्रकरण की जांच सौंपी गई है।

विशाखा समिति गठित की गई है, जिसमें तीन नामित सदस्य, एक पुरुष व एक महिला सदस्य शामिल हैं।समिति को एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

आरोपी आशुतोष सिंह का कहना है यह प्रकरण पुराना है। नर्स महीनों ड्यूटी पर नहीं आती। महीने में एक-दो दिन हाजिरी लगाती है, लेकिन सैलरी पूरे महीने की चाहती है। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। सीएमओ ने स्टाफ नर्स के खिलाफ भी जांच टीम गठित करने की बात कही है।

अब मामला जांच समिति के पाले में है। सवाल है क्या सच सामने आएगा? या यह भी लीपापोती के धुंध में खो जाएगा।

पैसे के विवाद की आड़, लेकिन सामने आया लव जिहाद और छलावे का सच!

# लव जिहाद : मोहम्मद सलीम ने रूपा को गला घोंटकर मार डाला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**नई दिल्ली।** देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर लव जिहाद की दिल दहला देने वाली घटना से दहक उठी है। पश्चिमी दिल्ली के डाबड़ी इलाके में रहने वाले 35 वर्षीय दर्जी मोहम्मद सलीम ने 22 वर्षीय हिन्दू युवती रूपा की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवती का शव बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया। दो दिन बाद जब शव सड़ा-गला हाल में बरामद हुआ तो हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई। पुलिस ने आरोपी सलीम को उत्तर प्रदेश के हरदोई से गिरफ्तार कर लिया है।

**कैसे हुआ हत्या का खुलासा :** रूपा 21 अगस्त की सुबह घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। उसकी मां ने उसी दिन गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 23 अगस्त को जब बोरे में युवती का शव मिला, तो पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में रूपा आखिरी बार महावीर एन्क्लेव स्थित सलीम के साथ एक इमारत में जाती दिखाई दी। कुछ देर बाद कैमरे में सलीम बाहर निकला–हाथ में बोरा, जिसमें रूपा का शव छिपा था। शव को बाइक पर ले जाते समय बोरा फिसला, घबराए सलीम ने शव को नाले में फेंक दिया और हरदोई भाग गया।

**पैसों का विवाद या लव जिहाद:** पुलिस की शुरुआती जांच में पैसे का लेन-देन हत्या का कारण बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का कहना है कि यह मामला केवल पैसों का नहीं, बल्कि लव जिहाद और छलावे से जुड़ा है। आरोपी सलीम लंबे समय से युवती से जुड़ा हुआ था। वह उसे अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण और शोषण की साजिश कर रहा था। जब युवती ने पैसे और रिश्ते को लेकर सवाल उठाए, तो उसने उसकी जान ले ली।

**हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश :** घटना से क्षेत्र में गुस्सा फैल गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में लव जिहाद एक गंभीर खतरा बन चुका है। कभी शादी के नाम पर, कभी पैसों के बहाने और कभी दोस्ती का ढोंग रचकर निर्दोष हिन्दू बेटियों को फंसाया जा रहा है।

स्वराज इंडिया का स्पष्ट मत है कि यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति पर सीधा प्रहार है। ऐसे मामलों में लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून, त्वरित न्याय और दोषियों को कठोर दंड देना आवश्यक है। रूपा जैसी बेटियों की सुरक्षा तभी संभव है जब देश में धर्म के नाम पर होने वाले छलावे और धोखे पर निर्णायक प्रहार किया जाए।

## सीएम योगी ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण

**गाजीपुर।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह वाराणसी में जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद गाजीपुर जिले में गंगा में बाढ़ का प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर गंगा में आई व्यापक बाढ़ के प्रभाव का अवलोकन किया और इस बाबत अधिकारियों से बातचीत कर व्यापक रूप से प्रभावितों की मदद के लिए निर्देशित किया।

बाढ़ की विभीषिका का आकलन करने के लिए सीएम हेलीकॉप्टर से वाराणसी से गाजीपुर की ओर रवाना हुए तो गाजीपुर जिला प्रशासन की टीम भी सक्रिय हो उठी। आनन फानन प्रशासनिक अधिकारी भी फील्ड की ओर रवाना हुए और सीएम के दौरे की निगरानी में प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट नजर आए। सीएम कार्यालय से जानकारी साझा कर बताया गया है कि सीएम ने बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।

खींच दी लकीर

कोर्ट ने उन टैरिफ को खारिज कर दिया जिन्हें ट्रंप ने 'नेशनल इमरजेंसी' घोषित कर कई देशों पर थोप दिया था

# कोर्ट ने किया खारिज, अब ट्रंप के टैरिफ का क्या होगा?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

**नई दिल्ली।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकतीं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप की व्यापार नीतियों ने अमेरिकी कारोबारियों, ग्लोबल मार्केट और उपभोक्ताओं में असमंजस और महंगाई की आशंका बढ़ा दी है। फेडरल अपील कोर्ट ने उन टैरिफ (आयात शुल्क) को खारिज कर दिया जिन्हें ट्रंप ने 'नेशनल इमरजेंसी' घोषित कर कई देशों पर थोप दिया था। कोर्ट ने साफकहा कि राष्ट्रपति को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि वे कांग्रेस (सदन) की मंजूरी के बिना भी विदेशी सामानों पर टैक्स लगा सकते हैं।दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वे कांग्रेस को दरकिनार कर दुनिया भर के देशों पर भारी-भरकम टैरिफ (आयात शुल्क) थोप सकते हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने 'लिबरेशन डे' बताते हुए लगभग सभी ट्रेड पार्टनर्स पर 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफलगाया था। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा ज्यादा था, उन पर 50 प्रतिशत तक के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए। बाद में उन्होंने 90 दिनों के लिए इन टैरिफ को निलंबित कर बातचीत का मौका दिया। जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने समझौते कर लिया, जबकि कुछ देशों पर भारी टैरिफ जारी रहा। उदाहरण के तौर पर लाओस पर 40% और अल्जीरिया पर 30% टैरिफ लगाया गया।

ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का हवाला दिया था और लंबे समय से चल रहे व्यापार घाटे को 'राष्ट्रीय आपातकाल' घोषित किया था। जबकि अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैक्स और टैरिफ लगाने की मूल शक्ति कांग्रेस के पास है। लेकिन धीरे-धीरे यह शक्ति राष्ट्रपति को भी दी जाती रही है। ट्रंप ने इसका अधिकतम इस्तेमाल किया।

### अदालत ने क्यों रोका?

ट्रंप प्रशासन ने दलील दी थी कि 1970 के दशक में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी इसी तरह आपातकालीन स्थिति में टैरिफलगाने की छूट दी गई थी। लेकिन न्यूयॉर्क की ट्रेड कोर्ट ने मई में इसे खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप के 'लिबरेशन डे टैरिफ कानून के तहत दी गई शक्तियों से बाहर हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने यही कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को 'असीमित अधिकार' देने का इरादा कभी नहीं जताया था।

### क्या हैं ट्रंप के पास दूसरे विकल्प?

**1974 का ट्रेड एक्ट:** इसके तहत व्यापार घाटे से निपटने के लिए सीमित शक्ति है। कानून में शर्त है कि टैरिफ15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकते और सिर्फ 150 दिनों तक ही लगाए जा सकते हैं, वह भी उन्हीं देशों पर जिनके साथ अमेरिका का बड़ा व्यापार घाटा है। फिलहाल, अपील कोर्ट के फैसले ने ट्रंप की मनमाने 'टैरिफ पॉलिसी' पर रोक लगा दी है। अब अंतिम फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा कि ट्रंप को भविष्य में विदेशी सामानों पर टैक्स लगाने की कितनी छूट मिलेगी।